मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- शिक्षा का सत्यानाश करने की होड़ — 3
- सरकारी डाक सेवा केवल पासवानों के लिये
- विकल्पहीनता का संकट — 4
- गतांक की चीर-फ़ाड़
- परीक्षा का दबाव और कारण — 5
- ''भारत ने किसी को साम्प्रदायिकता नहीं दी''
- विधायक सीमा त्रिखा के वायदे और इरादे — 8
- खट्टर सरकार द्वारा मज़दूरों पर हमला

वर्ष 29 अंक 5 फरीदाबाद, शनिवार, 16-31 जनवरी 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

गदपुरी टोल नाका: रिलायंस का लाइसेंसी डाका

राज चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का, धीरु भाई अम्बानी की कम्पनी रिलायंस की लूट सदैव कायम रही। उनकी मृत्यु के बाद अब उनके दोनों बेटों-मुकेश व अनिल द्वारा की जा रही खुली लूट बेहिसाब बढती जा रही है। और तो और भारत के महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी वर्ष 2014 की अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया था पर लूट बदस्तूर कायम रही।

मज़दूर मोर्चा, फ़रीदाबाद ब्यूरो

दिल्ली से आगरा तक के राजमार्ग को 6 लेन का बनाने में अनिल अम्बानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रेक्चर कम्पनी द्वारा किये गये घोटाले को कैग द्वारा उजागर किये जाने के बावजूद इस चोर कम्पनी के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के बजाय मोदी की भाजपाई सरकार ने उसकी लूट को और बढाने के लिये एक और टोल नाका वल्लभगढ़ व पलवल के बीच गदपुरी पर लगाने का लाइसेंस दे दिया। यानी कि अब पलवल तक जाने वाले भी अम्बानी की लूट का शिकार बना करेंगे। विदित है कि अब तक इस मार्ग पर कुल दो टोल नाके-पलवल से आगे बंचारी के पास व मथुरा से आगे सक्रिय लूट-केन्द्र के रूप में थे।

उक्त दोनों टोल नाके रिलायंस कम्पनी को 16 अक्टूबर 2012 को सरकारी खैरात में मिल गये थे, राजमार्ग को चौड़ा करने के नाम पर। जबकि नियम यह है कि काम पूरा करने के बाद ही टोल वसूली शुरू होती है लेकिन तत्कालीन (कांग्रेसी) सरकार ने काम पूरा तो दूर शुरू करने से पहले यह लूट का परमिट जारी कर दिया था। वर्ष 2014 की कैग रिपोर्ट के अनुसार इस कम्पनी ने पहले वर्ष में ही जनता से लूटे 120 करोड़ में से 78 करोड़ रुपये तो सीधे-सट अपनी म्यूचवल फ़ंड कम्पनी में डाल दिये बाकी इधर-उधर खर्च किये गये रूपयों को फ़र्जीवाड़े से सड़क पर खर्च दिखाये। सड़क पर खर्चे का फ़र्जी हिसाब तैयार किया गया। मशीनें व आदमी काम पर लगे दिखाये गये जबकि उस दौरान वास्तव में कहीं कोई काम सड़क पर हुआ ही नहीं था। कैग रिपोर्ट से उज़ागर इस फ़र्जीवाड़े के लिये कम्पनी को तुरंत ब्लैक लिस्ट करने के साथ-साथ इस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये था पर जब लुटेरे के नाम के आगे अम्बानी जुड़ा तो फ़िर किसी की क्या मज़ाल!

राजमार्ग एवं परिवहन मन्त्री नितिन गड़करी आये दिन कहते हैं कि टोल टैक्स की वसूली केवल काम पूरा होने के बाद ही शुरू की जा सकती है। उधर स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल गूजर बदर पुर बार्डर वाले टोल टैक्स को, चुनाव से पूर्व, जजिया कर बता कर इसे हटाने की मांग कर रहे थे। इसके समर्थन में

धरना प्रदर्शन भी किये गये। लेकिन अब? बदरपुर बार्डर वाला जजिया तो रहा ज्यों का त्यों है ही, गदपुरी में एक और नया जजिया भी लगाने जा रही है उनकी सरकार। अपनी सफ़ाई में पूरी बेशर्मी के साथ, कृष्णपाल जी फ़र्माते हैं कि ये सब करार तो उनकी पूर्ववर्ती कांग्रेस कर गयी थी। एक सरकार द्वारा किये गये करारों को निभाना दूसरी सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। बड़ी 'सही' बात कही मन्त्री जी ने। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठना लाजमी है कि फ़िर सरकार बदलने की जरूरत ही क्या है? वही सरकार चलती रहती।

गदपुरी टोल को लेकर उस (पृथला) क्षेत्र के अब भाजपाई बने विधायक टेकचन्द शर्मा थोड़ा विरोध का नाटक जरूर कर रहे हैं। बसपा की टिकट पर चुनाव जीत कर भाजपा सरकार की गोद में बैठे टेकचन्द यदि ईमानदारी से विरोध पर उतर आयें तो यह टोल नाका किसी सूरत में नहीं बन सकता लेकिन सर्वविदित है कि उनका यह विरोध एकदम नकली एवं दिखावा मात्र है जिसके आधार पर वे सरकार के साथ-साथ रिलायंस कम्पनी से भी मोटी सौदेबाज़ी कर सकेंगे।

यूं विरोध के नाम पर थोड़ी-बहुत चूं-चपड़ चौटाला पार्टी भी कर रही है, लेकिन हकीकत में कुछ करती नज़र नहीं आ रही। करने के नाम पर केवल बयान बाज़ी तक ही सीमित है यह पार्टी भी। कांग्रेस की तो आवाज उठाने की हिम्मत कहां? जबकि वस्तुस्थिति यह है कि यदि सौ आदमी भी सड़क पर उतर आयें तो सरकार की हिम्मत नहीं इस टोल नाके को लगाने की और जनता को लूटने में योगदान की।

कमीशन-तराजू में तुलते टोल नाके

मई 2014 में मोदी ने सत्ता कब्जाई थी। तुरन्त बाद की घोषणाओं में सड़क एवं परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी के मन्त्रालय की आम जन के मतलब की घोषणा भी शरीक थी कि राजमार्गों पर चलने वालों को टोल टैक्स तभी देना पड़ेगा जब राजमार्ग पूरी तरह बनकर इस्तेमालशुदा हो जायें। इसके लिये राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन का प्रारूप भी अक्टूबर 2014 में ही तैयार कर लिया गया। लेकिन तब से यह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सर्वविदित है कि राजमार्गों के निर्माण एवं विस्तार परियाजनाओं से सत्ताधारी गिरोह आराम से जनता का प्रतिवर्ष लाखों करोड़ डकार जाते हैं। नितिन गडकरी तो इस खेल का पुराना खिलाड़ी ठहरा। उसके नेतृत्व में राजमार्ग बनने की गति भी तेज़ हो गयी है और साथ ही कमीशन खाने और लूट नाके लगाने की भी।

ख़बर दार

'आप' की धरपकड़ और अपनी कमाई में 'स्वतंत्र'!

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी ने नव वर्ष की प्रेस वार्ता में दावा किया कि दिल्ली के लोग बेहद भाग्यशाली हैं कि दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार का नियन्त्रण न हो कर भारत सरकार का है। बस्सी के मुताबिक इससे दिल्ली पुलिस पर स्थानीय राजनीतिक दबाव नहीं काम करता और वह स्वतंत्र रूप से काम कर पाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, जिनके नियन्त्रण में फ़िलहाल दिल्ली पुलिस है, के पास रोज़ाना के काम में दखलंदाज़ी का समय और अवसर नहीं होता। पेश है दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लकर बस्सी से एक काल्पनिक साक्षात्कार।

म.मो.-आप वासत्व में कितने स्वतंत्र हो कमिश्नर साहब? क्या सिर्फ़ 'आप' के विधायकों-मन्त्रियों को खोज-खोज कर पकड़ने के लिये?

बस्सी-हमने जितने भी पकड़े हैं सबके खिलाफ़ आपराधिक मामले पाये गये। उन्हें पकड़ कर दिल्ली पुलिस ने क्या ग़लत किया।

म.मो.-यह तो ठीक है। लेकिन 'आप' से पहले कांग्रेस पार्टी 15 वर्ष शासन में रही। उनकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व अन्य मन्त्रियों व विधायकों के विरुद्ध गंभीर आरोप थे। उन मामलों में आपने अपनी 'स्वतंत्रता' प्रदर्षित नहीं की?

बस्सी-हम केवल स्वतंत्र हैं, अराजक नहीं कि हर किसी को पकड़ते चलें। 'आप' वाले तो हर किसी पर आरोप मढ देते हैं। पर हम आदमी देख कर पकड़ते हैं।

म.मो.-तभी आपने भाजपाइयों और अम्बानियों को भी बख्श रखा है। कैग रिपोर्ट के अनुसार अम्बानी की बिजली कम्पनी ने 8 हज़ार करोड़ रुपये ठगी द्वारा जनता से वसूले हैं। इसी तरह केन्द्रीय भाजपाई मन्त्री वी के सिंह ने दलितों को कुत्ते का पिल्ला कहा और ज्योति निरंजन ने मुसलमानों को हरामजादे कहा। इन पर कार्यवाही करने में आपकी स्वंतंत्रता कहां चली गयी?

बस्सी-फ़रवरी में रिटायर हो रहा हूं। उसके बाद भी तो नौकरी चाहिये। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बेशक हमारे रोज़मर्रा के काम में दखल न दें, पर मुझे अगली नौकरी तो उनहोंने ही देनी है।

म.मो.-दिल्ली पुलिस में मलाईदार तैनातियों के लिये पैसों का लेन-देन होता है। ट्रैफ़िक पुलिस की बंधी-बंधाई कमाई बदस्तूर जारी है। इन्हें रोक पाने में क्या आप स्वतंत्र नहीं हैं?

बस्सी-मैं तो केवल अपने आप को रोक पाने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं। आप पत्रकार हो कर भी दिल्ली पुलिस के लिये वही भाषा बोल रहे हो जो केजरीवाल एंड कम्पनी बोलते हैं। उन्होंने शुरू में हमारे एक सिपाही को घूस लेते पकड़ा था। हमने उस सिपाही से उन पर हाई कोर्ट में केस करवा दिया। अच्छा हो आप भी सावधानी से सवाल करें।

म.मो.-सम-विषम स्कीम लागू करने में तो आपकी पुलिस ने केजरीवाल सरकार को पूरा सहयोग दिया?

बस्सी-वह तो देना ही था। इस स्कीम से हमारे पुलिस वाले, विशेषकर ट्रैफ़िक पुलिस वाले बेहद खुश हैं। अन्त में चांदी तो उन्होंने ही काटनी है।

मोहम्मद तुग़लक को यह सुविधा नहीं थी...

मध्ययुगीन सिरफ़िरे शासक, दिल्ली के सुलतान और तुगलक वंश की शान मोहम्मद तुग़लक को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी कि वह अपनी बेसिर-पैर की योजनाओं को 'प्रयोग' का नाम दे पाता। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारतीय राजनीतिक क्षितिज के नवोदित सितारे अरविंद केजरीवाल को यह सुविधा प्राप्त है कि वे अपनी बड़ी से बड़ी सनक को भी 'प्रयोग' का नाम दें।

तुगलक ने चुस्त प्रशासन के नाम पर दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने और वापस लाने में लाखों दिल्ली वासियों की कई बरस तक ऐसी-तैसी कराई। केजरीवाल ने प्रदूषण कम करने के नाम पर सम-विषम प्रयोग एक से पन्द्रह जनवरी तक चला कर दिल्ली और आस-पास के निवासियों का जीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। एक दिन सम नम्बर की और दूसरे दिन विषम नम्बर की गाड़ियां चलाने की समूची जिद को महज़ कार-पूल व स्कूल बसों के दम पर पूरा करने का प्रयास शेखचिल्ली का सपना ही कहा जा सकता है। न तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में कोई बेहतरी की गयी और न ही आपातकालीन जरूरतों का ध्यान रखा गया। सारे एनसीआर से व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, सरकारी व अदालती कामकाज के लिये आने वालों को तो पूरी तरह भुला ही दिया गया। दिल्ली में कुछ स्थानों पर लोग कहते सुने गये कि इस स्कीम के चलते ट्रैफ़िक जाम कम हुए हैं। पर वास्तविकता यह है कि ये जाम कुछ इलाकों से शिफ्ट हो कर कुछ अन्य इलाकों में चले गये। साथ ही रात 8 बजे के बाद, जब स्कीम में छूट होती थी, ट्रैफ़िक अचानक बढ जाता था। सबसे बुरी स्थिति दिल्ली के बॉर्डरों पर रही जहां पड़ोसी राज्यों में लम्बे-लम्बे ट्रेफ़िक जाम लगे रहे।

आम सवाल पूछा जा रहा है कि यह प्रदूषण कम करने की स्कीम थी या वाहनों की भीड़ कम करने की? इस दौरान हज़ारों का चालान कर करोड़ों रुपये वसूले गये। परिवहन मन्त्री गोपाल राय ने कहा कि इस धन का इस्तेमाल साइकिल खरीदने में सब्सिडी देने के लिये किया जायेगा। इस अक्ल के कोल्हू से कोई पूछे कि जिन दिल्ली वासियों के पास साइकिलें हैं उन्हें चलने का रास्ता तो दे दो। वे रोज़ अपनी जान को दांव पर लगा कर ही सड़क पर निकल पाते हैं।

यदि यह स्कीम लागू ही करनी थी तो बजाय चालान की तलवार लटकाने के प्रोत्साहन की रणनीति इस्तेमाल की जा सकती थी। मसलन सम वाले दिन विषम कार भी सड़क पर आने दी जाती बशर्ते उसमें कम से कम 3 सवारियां हों। इसी तरह 4 सवारियों वाली कार को फ्री पार्किंग दी जा सकती थी। हालांकि सौ बात की एक बात यह कि सम-विषम स्कीम न प्रदूषण और न ट्रैफ़िक जाम को कम करने का नुस्खा है।